



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-08(03/53)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही राज्यहित से जुड़ी इन योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सांइस सिटी के निर्माण के लिए 134 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ही दून लाइब्रेरी के लिये 7.50 करोड़ मंजूर किये है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की बहुउद्देश्यी जमरानी बांध परियोजना के लिये भी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मंसूरीवासियों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए उनके द्वारा निरन्तर केन्द्र सरकार से समन्वय किया जा रहा था इसी का प्रतिफल रहा कि मसूरी की पेयजल समस्या के समाधान के लिए पी.एम.ओ द्वारा शनिवार 9 मार्च तक 124 करोड़ की धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दून लाइब्रेरी में उत्तराखण्ड का साहित्य भी उपलब्ध कराया जायेगा ताकि यहां अध्ययन करने वाले छात्रों को अपनी संस्कृति से परिचित होने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी मदद मिल सकेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया विकासनगर में लगभग 100 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास

- विकासनगर-हर्बटपुर में बनायी जायेगी सीवर लाईन व सफाई की योजना।
- विकासनगर से कुन्माड़ी एन एच मार्ग का किया जायेगा सुदृढीकरण।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को विकासनगर में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 100 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासनगर-हर्बटपुर में सीवर लाईन व सफाई की योजना बनाई जायेगी। छोटा पत्थर, यमुना नहर से कुमेट तक लिफ्ट सिंचाई योजना पूर्ण की जायेगी। विकासनगर से कुन्माड़ी एन एच मार्ग का सुदृढीकरण किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जिन योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया उनमें नाबार्ड के अन्तर्गत विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम पपडियान, तौलीभूड लांघा, ग्राम पुष्ठा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों के स्प्रिंकलर आधारित 1611.88 लाख लागत की लिफ्ट सिंचाई योजना, नाबार्ड के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में 1155.06 लाख लागत की कटापत्थर नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग की योजना, नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में 179.40 लाख लागत की क्षतिग्रस्त बंडवा नहर के पुनर्निर्माण की योजना, राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में 72.59 लाख लागत की टी-स्टेट से विकासनगर तहसील के मध्य उदियाबाग नाले से जल निकासी की योजना का शिलान्यास तथा नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड में 622.82 लाख लागत की ढकरानी नहर बाईपास मार्ग के सुदृढीकरण की योजना का लोकार्पण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत विकासनगर क्षेत्र में जिन मोटर मार्गों का शिलान्यास किया गया उनमें नगरपालिका हर्बटपुर के वार्ड नं0 2 में (आदर्श विहार के आन्तरिक) मार्ग का पुनः निर्माण व सुदृढीकरण कार्य (लागत 149.18 लाख)। जीवनगढ़ में कैनाल रोड से साई मन्दिर तक मार्ग निर्माण तथा एन.एच. 507 से गौरी शंकर मंदिर होते हुए जकारिया मस्जिद तक मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य। (लागत 44.39 लाख)। विकास नगर डाक पत्थर रोड से नवाबगढ़ होते हुए शक्ति नहर तक एवं जकारिया मस्जिद के आगे से वाल्मिकी मंदिर डाकपत्थर मार्ग तक लिंक मार्ग तथा शक्ति नहर बाईपास से चन्द्र मोहन के घर तक मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य। (लागत 154.37 लाख)। बरोटीवाला अम्बाड़ी मार्ग का कार्य (लागत 258.63 लाख)। ग्राम पंचायत लम्बरपुर में जामनखाता मुख्य मार्ग से खेड़ा बाबा एवं प्रताप चन्द की गौशाला तक सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम पंचायत बालूवाला में लांघा मार्ग से प्राईमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग व लांघा मार्ग से रफीक व लियाकत आदि के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (लागत 124.60 लाख)। ग्रामसभा बाड़वाला से राजस्व ग्राम राजावाला तक सम्पर्क मार्ग एवं केदारावाला चौक से शहीद के घर तक तथा केदारावाला चौक से बस स्टैण्ड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। (लम्बाई 2.914 किमी लागत 196.95 लाख)। बरोटीवाला विकासनगर मार्ग के कि.मी. 4.00 से उदयाबाग तक एवं वार्ड नं 2 में मुख्य से शिव मंदिर तथा आशाराम पैन्थूली आदि के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (लागत 189.41 लाख) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। प्रदेश के विकास के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर सरकार कार्य कर रही है। अभी रानीपोखरी में 22वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। डोईवाला में सीपेट की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चों को सौ फीसदी प्लेसमेंट मिलेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किच्छा व लालढांग में दो नए मॉडल डिग्री कॉलेजों व पौड़ी के पैठाणी में प्रदेश के पहले वोकेशनल कॉलेज का शिलान्यास किया है। इन संस्थानों के लिए बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है। ये तमाम कोशिशें प्रदेश के लिए न केवल रोजगारपरक शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। बल्कि उत्तराखण्ड को उच्च शिक्षा का हब बनाने में भी मददगार होंगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की शुरुआत की है। जिससे प्रदेश के लगभग 55 हजार युवा रोजगार से जुड़ सकेंगे। उत्तराखण्ड में जल्द ही साइंस सिटी बनाई जायेगी। साइंस सिटी बनाने के लिए केन्द्र से स्वीकृति मिल चुकी है। साइंस सिटी के लिए सुद्धोवाला में 26 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इससे बच्चों को विज्ञान के आधुनिक तौर-तरीकों की जानकारी के साथ ही अन्वेषण करने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। विभिन्न रोजगारपरक नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हमने हर स्तर पर रोजगार सृजन के प्रयास किए हैं। युवाओं को राज्य की प्रगति से जोड़ने के उद्देश्य से 06 मार्च को परेड ग्राउण्ड में युवा उत्तराखण्ड उद्यमिता एवं रोजगार की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 14 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया व 52 कॉलेजों के 13 हजार से अधिक छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। छात्र-छात्राओं से संवाद भी किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में 1137 डॉक्टरों की भर्ती की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन को रोकने व स्वरोजगार की ओर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न महिलाओं को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उन्ही योजनाओं की घोषणा करते हैं जो पूर्ण हो सके। यह मुख्यमंत्री की बेहतर कार्यप्रणाली का द्योतक है। इसका यह भी उदाहरण है कि विकास नगर क्षेत्र के लिए

की गई घोषणायें 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए 30 करोड़ की पेयजल योजनाये स्वीकृत की है। दो साल के अन्दर इस क्षेत्र में विकास के नये द्वार खुले हैं। क्षेत्र की बदहाल सड़कों का सुदृढीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करइस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि का केन्द्र बनाने में भी मदद की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सड़कों व पुलों के निर्माण से विकास के नये द्वार खुलेंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर ऑल-वेदर रोड के अन्तर्गत लंगसी (गुलाबकोटी) से पैनी बैंड तक लोनिवि की जो पुरानी सड़क बनी हुई है, को आल वेदर रोड से जोड़ने व चुंगी से ओ0एम0जी तक बाईपास बनाये जाने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को लिखे पत्र में कहा है कि इससे गुलाबकोटी से हेलंग की दूरी लगभग 06 कि0मी0 कम हो जायेगी जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

ज्ञातव्य है कि जोशीमठ (ज्योर्तिमठ) बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमण्डल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र से मुख्यमंत्री आवास में भेंट कर उन्हें इस सम्बन्ध में अपना मांग पत्र सौंपा था। इसी सन्दर्भ में क्षेत्रीय जनभावनाओं के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अपेक्षी की है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाले जनपद उधम सिंह नगर की हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशयों में 200 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी), नई दिल्ली व सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड एवं उरेडा के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। एमओयू पर सेकी की ओर से प्रबन्ध निदेशक जे0एन0स्वान तथा सिंचाई विभाग की ओर से श्री ए0के0दिनकर तथा उरेडा की ओर से मुख्य परियोजना अधिकारी श्री ए0के0त्यागी द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड इनवेस्टर समिट के दौरान फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना राज्य के विभिन्न जलाशयों पर कराये जाने के संबंध में निजी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था। उक्त के क्रम में प्रथम चरण में सेकी द्वारा अपने संसाधनों से रु1000 करोड़ का निवेश कर इन जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश का प्रथम सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट होगा तथा इसे 18 माह में सेकी द्वारा पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। इसकी लागत रु1000 करोड़ है। इससे 30 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की बिजली जरूरते पूरी होने के साथ ही निवेश के संसाधन भी बढ़ेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त, श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव सिंचाई डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख एवं सचिव ऊर्जा/वैकल्पिक ऊर्जा श्रीमती राधिका झा उपस्थित थे।

देहरादून 08 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो)**प्रेस नोट-05(03/50)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड लेखा परिक्षा प्रबन्धन प्रणाली की ऑन लाइन वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहल से विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों की आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ ही पारदर्शिता भी आयेगी। इससे सम्बन्धित सूचनाओं के प्रेषण व क्रियान्वयन में भी तेजी आयेगी।

इस अवसर पर सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने बताया कि इस वेबसाइट से लेखा परीक्षा के कार्यों में तेजी आयेगी, विभिन्न विभागों की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित टिप्पणियां भी ऑन लाइन तैयार होगी। सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारी इससे जुड़ जायेंगे तथा उनके विवरण भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण राजस्व प्रबन्धन एवं वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किये जाने में भी मदद मिलेगी। इस वेबसाइट को एनआईसी के सहयोग से तैयार किया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त, श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव सिंचाई डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख एवं सचिव ऊर्जा/वैकल्पिक ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, एनआईसी एवं वित्त व लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 08 मार्च, 2019 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-04(03/49)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य हित में विभिन्न विभागों में जिन महानुभावों को राज्य मंत्री स्तर का दायित्व सौंपा गया है उनमें -प0 राजेन्द्र अंधवाल को उपाध्यक्ष गो सेवा आयोग, रिपुदमन सिंह रावत को उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण समिति, वीरेन्द्र सिंह बिस्ट को अध्यक्ष उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार समिति, राजकुमार पुरोहित को अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद, सुरेश परिहार को अध्यक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विश्वास डाबर को अध्यक्ष राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इससे विभिन्न विभागों के कार्यों एवं अनुश्रवण में गति मिलेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बट्टी केदार सहयोग समिति द्वारा शमसेरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिये लिंगानुपात का सही होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन्म के समय से ही लड़का व लड़की में भेद करना अपराध है। यह भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नारी को सम्मान देने की पुरातन परम्परा रही है। हम देश, गंगा, गाय को मा के रूप में सम्मान देते हैं। धरती के कंकड में हम ईश्वर को देखते हैं। ऐसे देश में जन्म के समय में ही लड़की व लड़के में भेद करना सामाजिक विकृति की तरह है। उन्होंने दून अस्पताल में पैदा हुए बेटा-बेटी के जन्म के बाद बेटी को मां के द्वारा दूध न पिलाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी शिक्षित होने के बाद भी इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मां-बहिनों को आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने अपने अमेरिका भ्रमण के अवसर पर एक बच्ची में मां के स्वरूप को देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी-बचाओ-बेटी- पढाओ की सार्थकता के लिये अब नन्दा गोरा कन्या धन योजना के तहत बच्ची के जन्म पर 5 हजार के बजाए 11 हजार तथा इण्टर के बाद 21 हजार के बजाए 51 हजार की राशि प्रदान की जाएगी ताकि बच्चियां पढ़ लिख सकें तथा सामाजिक रूप से समाज में समान से जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल करने वाली दायी मां को अब 500 के बजाए 1000 रु प्रतिमाह मिलेंगे। जबकि आशा कार्यकर्त्रियों को 5 हजार के स्थान पर 17 हजार वार्षिक मानधन दिया जाएगा।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति श्री नरेश बंसल ,पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिहरी के जिला अस्पताल बौराडी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर एवं देवप्रयाग में हिमालयन अस्पताल जौलीग्रान्ट प्रदान की जायेगी चिकित्सा सेवाएं।

- मुख्यमंत्री ने किया योजना का शुभारम्भ।
- प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हिमालयन हास्पिटल द्वारा जिला चिकित्सालय बौराडी टिहरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर एवं देव प्रयाग में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं का शुभारम्भ किया। इस प्रकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई महत्वपूर्ण हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद टिहरी में चिकित्सा सेवाओं का संचालन हिमालयन अस्पताल जौलीग्रान्ट द्वारा आज से प्रारम्भ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैल्थ सिस्टम परियोजना की इस गतिविधि को टिहरी क्लस्टर के नाम से संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जनपद के लिए उपलब्ध की जायेंगी और जिला चिकित्सालय बौराडी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर एवं देवप्रयाग में हिमालयन अस्पताल के चिकित्सक तैनात रहेंगे इसके अतिरिक्त तीन सचल चिकित्सा वाहन भी संचालित किए जायेंगे जिनके द्वारा क्षेत्र में रोगियों की जांच एवं उपचार प्रदान करने का कार्य किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिये निजी अस्पतालों की भी सेवायें ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भी योजनाये बनायी गई है। टेलीमेडिशन, टेली रेडियोलॉजी सहित जिला चिकित्सालयों में आईसीयू की स्थापना जैसी पहल इसमें मददगार होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने टिहरी क्लस्टर के अलावा पौड़ी जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को भी इसी तर्ज पर चलाने का निर्णय लिया है जिसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैण तथा बीरौखाल को भी लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत सुदृढ़ करने का कार्य किया जायेगा।

सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने बताया कि लोक निजी सहभागिता के अनुसार संचालित की जाने वाली इस परियोजना के अन्तर्गत अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लाभार्थियों को भी निःशुल्क उपचार प्रदान किया जायेगा और रु 5 लाख तक के अन्तर्गत अस्पताल में उपलब्ध सभी प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मरीजों को मिलेगी।

जिला चिकित्सालय में हिमालयन अस्पताल के 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं के अतिरिक्त सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स रे तथा ई0सी0जी0 आदि प्रमुख जांचे उपलब्ध रहेंगी। जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनता को भी आवश्यकता अनुसार जिला चिकित्सालय की सभी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होगी और इन सेवाओं को सामुदायिक केंद्रों पर भी दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली तीनों सचल चिकित्सा वाहन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और जनता को प्राथमिक उपचार के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान की जायेगी। जिला चिकित्सालय में राज्य सरकार के सी0एम0एस0 स्तर का एक अधिकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर राज्य सरकार के नियमित मेडिकल ऑफिसर का प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा।

इस अवसर पर स्वामी राम हिमालयन अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज जौलीग्रान्ट के कुलपति डा. विजय धरमाना ने इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि अस्पताल में सभी प्रकार के प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जायेगी जिस हेतु 27 चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सी0एच0सी0 बेलेश्वर एवं देवप्रयाग में 8-8 चिकित्सक तैनात रहेंगे जबकि तीन सचल चिकित्सा वाहनों पर आकस्मिक सेवा हेतु 2 चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ की तैनाती की गई है। अस्पताल द्वारा सभी संवाएं सरकारी दरों पर पूर्व की भांति आम जनता को मिलेंगी और उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है- मुख्यमंत्री

- आशा कार्यकर्त्रियों के वार्षिक पारिश्रमिक को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार किया गया।
- दाई के मासिक पारिश्रमिक को भी 500 से बढ़ाकर किया गया 1000 रुपये।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां होगी अब हाईटेक-दिये गये स्मार्ट फोन।

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आशा कार्यकर्त्रियों के वार्षिक पारिश्रमिक को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार तथा दाई के मासिक पारिश्रमिक को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन व वजन मशीन का वितरण भी किया। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से स्मार्ट फोन दिये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड उत्तर भारत का पहला राज्य है, जहां सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए हैण्डवॉश मेनुअल, सांप सीढ़ी के खेल व सुनहरे हजार दिनों के मैनुअल का विमोचन किया। इसके अलावा प्रचार सामग्री इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन व कन्स्यूनिंग (आईईसी) का विमोचन भी किया गया। 08 से 22 मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़े का शुभारम्भ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वर्ष की थीम "नव परिवर्तन के लिए समान सोंचे, स्मार्ट बनें" रखी गई है।

शुक्रवार को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में नारी के प्रति जो सम्मान का भाव है, आज पश्चिमी देश भी इसका अनुसरण कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। किसी भी समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं व पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को संस्कार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ की होती है। बाल्यावस्था के शुरुआती 5 सालों में बच्चों पर संस्कारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मातृ शक्ति से अपील की है कि बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने की दिशा में भी सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि नन्दा गौरा योजना में परिवर्तन किया गया है। अब बच्ची के जन्म के समय 11 हजार व इण्टरमीडिएट करने के बाद स्नातक में प्रवेश के समय बालिका को इस योजना के तहत 51 हजार रुपये दिये जायेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पोषण अभियान व बेटी बचाओ अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी टिहरी सोनिका को पोषण अभियान व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून श्रीमती निवेदिता कुकरेती को सखी ई-रिक्शा लॉच में अहम योगदान व पोस्को में अपराधों के निवारण में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा पोष्टिक आहार व बेटी बचाओं में अच्छा कार्य करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

महिला सशक्तिकरण व बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक व मानसिक रूप से महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। देवभूति उत्तराखण्ड में तीलू रौतेली, गौरा देवी, टिंचरी माई जैसी वीरगनाओं ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है।

विधायक श्री गणेश जोशी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक सराहनीय कदम उठाये हैं। बेटियों को सशक्त कर की समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। मातृशक्ति का सम्मान व समानता का अधिकार ही समाज को उन्नति का मार्ग है।

मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में यहां की मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रही हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में अनेक पहल कर रही है।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार ने अनेक पहल की हैं। प्रधानमंत्री जी के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों में गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाये गये हैं।

इस अवसर पर श्री मूरत राम शर्मा उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण परिषद, श्री भगत राम कोठारी अध्यक्ष गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड, निदेशक आईसीडीएस सुश्री झरना कमठान, उपनिदेशक श्रीमती सुजाता डीपीओ देहरादून आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग